THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) and (b) Yes, Sir. Government have been providing financial assitancc to cooperatives of weaker sections. Under this scheme, assistance is being provided largely to the following existing/new cooperative societies:

(i) Labour Cooperatives; (ii) Forest Labour Cooperatives; (iii) Rickshaw Puller's Cooperatives; (iv) Washermens Cooperatives;

(v) Cooperatives of Vendors;

(vi Multi-professional cooperatives (comprising persons like berbers, cobblers, blacksmiths, hawkers, Washermen and vendors)..

The assistance is given in the form of loan and subsidy to the concerned cooperative societies through the respective State Government.

(c) The required information is given in the Statement *(see* below).

(d) The concerned primary societies have generally benefited from the assistance provided by the Government.

(e) The scheme for provided financial assistance to cooperatives of weaker sections is continuing and it is expected that more such societies will come forward to avail of this assistance through the State Government of Maharashtra.

Statement

Name of the Scheme	Year	No. and names of Societies	Total amount released (Rs in lakhs)
Assistance to Weaker Section Cooperatives	1995-96	(i) Shri Ganesh Gowandi Majoor Sah. Sanstha Chalis-gaon-Jalgaon	1.00
		(ii) Shri Datta Majoor Sah. Sanshta. Tal. Jamner District Jalgaon	1.00
		(iii) Shri Vit Chuna Utpadak Sah. Sanstha Wadaji Tal. Bhadgaon District Jalgaon.	1.00
			3.00
	1996-97	Nil	Nil
	1997-98	Nil	Nil

सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि को बढ़ावा दिया जाना

1673. श्री बलवंत सिंह रामूवालिया: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इंडियन फार्म फारेस्ट्री डेवलपमेंट कोआपरेटिव द्वारा देश में सहकारी संस्थाओं के आधार पर कृषि को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा गया है:

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की विस्तृत रूप -रेखा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने हेतु कोई कार्य-योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव में लघु और सीमांत किसानों को शामिल करते हुए कृषि के विकास के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) और (ख) इंडियन फार्म फारेस्ट्री डेवलपमेंट को आपरेटिव लि0 ने सहकारी संस्थाओं के आधार पर कृषि को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष प्रस्ताव नहीं भेजा है। तथापि, उसने देश के 10 राज्यों में सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से 50,000 हैक्टेयर परती भूमि को फार्म फारेस्ट्री के तहत लाने के लिए एक परियोजना प्रस्ताव परती भूमि विकास विभाग को भेजा है।

(ग) और (घ) परती भूमि विकास विभाग ने आर्थिक मामलों के विभाग से इस परियोजना को एक अंतर्राष्ट्रीय दाता अभिकरण के रूप में अर्थात् यू0एन0डी0पी0, एस0 आई0 डी0ए0, विश्व बैंक और जर्मन जैसी एजेन्सी को प्रस्तुतु करने का अनुरोध किया है। प्राथमिक सहकारी सोसायटियों , जो आई0 एफ0एफ0 डी0सी0 की सदस्य बन गई है, के पास छोटे और सीमान्त किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों की बडी संख्या में सदस्यता है ।

कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना

1674. श्री ईश दत्त यादवः
चौधरी हरमोहन सिंह यादवः

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो के दौरान राज्य-वार विकास कार्य संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस कार्य में कोई कठिनाई महसूस हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल):

(क) जी, हां।

(ख) विभिन्न राज्यों में कृषि विकास के लिए कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) भारत सरकार, आवधिक प्रगति रिपोर्टो, फील्ड दौरों, श्रेत्रीय अधिकारी की बैठकों, छमाही राष्ट्रीय सम्मेलनों/ क्षेत्रीय सम्मेलनों, आदि के माध्यम से विभिन्न कृषि विकास कार्यो की प्रगति की नियामित रूप से मानिटरिग और समीक्षा कर रही है।

विवरण

कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा राज्यों में कार्यन्वित की गई प्रमुख केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की सूची

क्र0स0	योजनाओं का नाम	राज्य जहां कार्यान्वित की गई
1.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-चावल	आंध्र प्रदेश, असम, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, मनीपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उडीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
2.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-गेहूं	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश
3.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-मोटे अनाज	गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम